एलपीजी सब्सिडी में बढ़ी पारदर्शिता : हरदीप

67 प्रतिशत उज्ज्वला लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा

लक्षित सब्सिडी प्रणाली को मिली मजबूती

नई दिल्ली, 5 अगस्त. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए वितरण और सब्सिडी हस्तांतरण को और अधिक कुशल, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. पहल (डीबीटीएल) स्कीम, आधार-आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और नकली कनेक्शनों को हटाने जैसे कदमों से लक्षित सब्सिडी प्रणाली को मजबूती मिली है.

पुरी ने बताया कि सभी एलपीजी वितरकों के लिए आईवीआरएस/एसएमएस आधारित रिफिल बुकिंग सिस्टम लागू किया गया है. इस सिस्टम के तहत उपभोक्ताओं को रिफिल बुकिंग, कैश मेमो और डिलीवरी की जानकारी एसएमएस के जरिए मिलती है, जिससे वे अपने लेन-देन को ट्रैक कर सकते हैं और गड़बड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. साथ ही, तेल विपणन कंपनियों ने डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) शुरू किया है, जो डिलीवरी के समय उपभोक्ता को एसएमएस के जरिए भेजा जाता है और डिलीवरी कर्मियों के साथ साझा करना अनिवार्य है, ताकि प्रमाणीकरण सुनिश्चित हो.

एलपीजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा वितरकों के गोदामों, शोरूमों और वितरण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाता है. क्षेत्रीय, जोनल और प्रादेशिक कार्यालयों के साथ-साथ एंटी-एडल्टरेशन सेल और विजिलेंस विभाग मिलकर इसकी निगरानी करते हैं.

12,000 निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शनों को किया जाएगा बंद

पुरी ने बताया कि आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन ने डीबीटी योजनाओं में लाभार्थियों की सटीक पहचान और दोहराव को कम करने में मदद की है. 1 जुलाई 2025 तक 67 प्रतिशत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो चुका है. नए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है. डुप्लीकेशन हटाने की प्रक्रिया के तहत 8.49 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन समाप्त किए गए हैं. जनवरी 2025 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, 12,000 निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शनों को बंद किया गया, जिनके उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद कोई रिफिल नहीं लिया था. 2024-25 में लगभग 194 करोड़ एलपीजी रिफिल वितरित किए गए, जिनमें से केवल 0.08 प्रतिशत मामलों में शिकायतें दर्ज हुईं, जो मुख्य रूप से सब्सिडी हस्तांतरण या वितरण में देरी से संबंधित थीं.

मॉयल ने वित्त वर्ष 26 में अब तक का सर्वोच्च जुलाई उत्पादन किया

नई दिल्ली, 5 अगस्त. मॉयल ने जुलाई 2025 में 1.45 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 11.4त्न की वृद्धि है. यह वित्त वर्ष 26 में अब तक का कंपनी का सर्वोच्च जुलाई उत्पादन है. भारी बारिश के बावजूद, अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान उत्पादन 6.47 लाख टन (7.8% वृद्धि), बिक्री 5.01 लाख टन (10.7त्न वृद्धि) और अन्वेषण ड्रिलिंग 43,215 मीटर (11.4% वृद्धि) रही. कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजित कुमार सक्सेना ने टीम को बधाई दी.

यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड

100 करोड़ का रोजाना लक्ष्य | **85 प्र.श. डिजिटल भुगतान में यूपीआई**

नई दिल्ली, 5 अगस्त.भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित दैनिक लेनदेन की संख्या पहली बार 70.7 करोड़ तक पहुंच गई है. यह उपलब्धि इस महीने की 2 अगस्त को हासिल की गई.

पिछले दो वर्षों में, दैनिक लेनदेन की संख्या दोगुनी हो गई है, हालांकि, पिछले वर्षों की तुलना में यह वृद्धि थोड़ी धीमी रही है. अगस्त 2023 में, यूपीआई प्रतिदिन लगभग 35 करोड़ लेनदेन दर्ज कर रहा था, जो अगस्त 2024 में बढ़कर 50 करोड़ दैनिक लेनदेन हो गया.

सरकार ने यूपीआई के लिए प्रतिदिन 100 करोड़ लेनदेन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, और उम्मीद है कि मौजूदा विकास दर के साथ यह प्लेटफॉर्म अगले वर्ष इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा. फिनटेक कंपनियों और भुगतान संघों के अनुसार, यूपीआई के बिजनेस मॉडल को अगले साल तक एक अरब लेनदेन हासिल करने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को फिर से लागू करना चाहिए. उन्होंने सरकार से प्रमुख व्यापारियों और उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए मामूली एमडीआर स्थापित करने का अनुरोध किया.

सरकार ने यूपीआई के लिए सब्सिडी को वित्त वर्ष 24 में लगभग 4,500 करोड़ रुपए से घटाकर वित्त वर्ष 25 में 1,500 करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन उसने एमडीआर की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भुगतान कंपनियों की एमडीआर मांग का समर्थन किया. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यूपीआई इंटरफेस को आर्थिक रूप से स्थायी बनाया जाना चाहिए. एमडीआर डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया के लिए बैंकों द्वारा व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क है. इसे दिसंबर 2019 में रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन पर माफ कर दिया गया था. आरबीआई गवर्नर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूपीआई ने दैनिक लेनदेन की मात्रा के मामले में वैश्विक भुगतान दिग्गज वीजा को पीछे छोड़ दिया है.

> यूपीआई अब भारत में सभी डिजिटल लेनदेन का लगभग 85% और दुनिया भर में सभी रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों का लगभग 50% संचालित करता है. जैसे-जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है, इस प्लेटफॉर्म में मासिक आधार पर 5-7% और सालाना आधार पर 40त्न की वृद्धि देखी जा रही है.

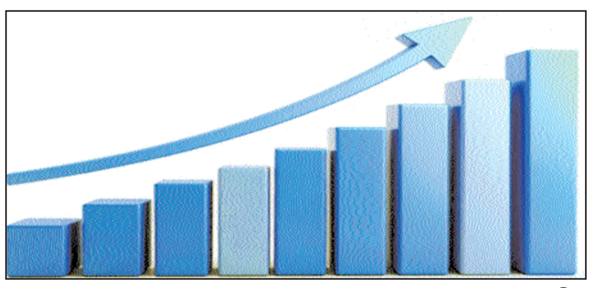

जुलाई में सर्विस सेक्टर में मजबूती

पीएमआई 60 .5 पर, वैश्विक मांग से मिली

नई दिल्ली, 5 अगस्त.भारतीय सर्विसेज की मांग में सुधार होने के कारण जुलाई में सर्विसेज सेक्टर में नए ऑर्डर, वैश्विक बिक्री और आउटपुट में सुधार देखा गया. यह जानकारी मंगलवार को एक निजी सर्वेक्षण में दी गई.

एचएसबीसी इंडिया के मुताबिक, जुलाई का सर्विसेज पीएमआई 60.5 रहा है, जो कि जून के आंकड़े 60.4 से मामूली रूप से अधिक है. यह अगस्त 2024 के बाद सर्विसेज पीएमआई का सबसे बड़ा आंकड़ा है. जब भी पीएमआई 50 से अधिक होता है तो यह वृद्धि को दिखाता है, जब भी यह 50 से कम होता है तो गिरावट को दर्शाता है.

एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि सर्विसेज पीएमआई 60.5 पर होना दिखाता है कि सर्विस सेक्टर में मजबूत रुझान बना हुआ है.

अडानी पोर्ट्स को 3,311 करोड़ रुपये का मुनाफा

अहमदाबाद, 05 अगस्त (वार्ता) बंदरगाह संचालन करने वाली अग्रणी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 3,311 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 3,107 करोड़ रुपये की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है. कंपनी ने मंगलवार को जारी पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों में बताया कि उसका राजस्व साल-दर-साल आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 9,126 करोड़ रुपये पर पहुँच गया. इस दौरान उसका लॉजिस्टिक्स कारोबार दोगुना हो गया और यह पिछले साल की समान तिमाही के 571 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,169 करोड़ रुपये पर पहुँच गया.

डिजिटल युग में जनसंपर्क की चुनौतियाँ

डीपफेक और फेक न्यूज बनीं नई बड़ी मुसीबत

AI, डेटा एनालिटिक्स जैसे कौशल अब अनिवार्य

24×7 मीडिया दबाव में बढ़ा पारदर्शिता का महत्व

नई दिल्ली, 5 अगस्त. जनसंपर्क पेशेवरों की अग्रणी संस्था जनसंपर्क सोसाइटी, दिल्ली ने डिजिटल युग में जनसंपर्क और कॉर्पोरेट संचार की चुनौतियाँ विषय पर एक महत्वपूर्ण वेबिनार का सफल आयोजन किया.

इस वर्चुअल कार्यक्रम में जनसंपर्क क्षेत्र के दिग्गजों ने डिजिटल दौर में उभरती चुनौतियों और उनसे निपटने की कारगर रणनीतियों पर गहन चर्चा की.वेबिनार में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट अफेयर्स) निशांत वर्मा और एनटीपीसी के महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) के. एम. प्रशांत ने मुख्य वक्ताओं के रूप में शिरकत की.

वेबिनार की मुख्य बातें

- **प्रामाणिकता बनाए रखना-** संचार में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर विश्वास और विश्वसनीयता कायम रखने के लिए.
- **नवीन कौशलों की आवश्यकता-** डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ृढ्ढ) और एल्गोरिदम के प्रभाव को समझना जनसंपर्क पेशेवरों के लिए अब अनिवार्य हो गया है.
- **सामग्री की रणनीतिक प्रस्तुति-** विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनुसार सामग्री को तैयार करना और प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि सूचनाओं की भीड़ में अपना संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके.
- **मूलभूत कौशलों की अहमियत-** अच्छा लिखना, पढ़ना और सुनना जैसी पारंपरिक क्षमताएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं.
- **एआई का सही उपयोग-** एआई को एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि मानवीय समझ और सामाजिक सोच के विकल्प के रूप में.

नीति आयोग का ई-मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च

नई दिल्ली, 5 अगस्त.नीति आयोग ने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (आईईएमआई) लॉन्च किया है, जो अपनी तरह का पहला उपकरण है. इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति को ट्रैक और बेंचमार्क करने के लिए विकसित किया गया है.

आईईएमआई तीन मुख्य विषयों में आने वाले 16 संकेतकों के आधार पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रैक करता है, उनका मूल्यांकन करता है और 100 में से अंक देता है. ये तीन मुख्य विषय हैं-

- बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परिवहन में विद्युतीकरण में हुई प्रगति.
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए विकास को ट्रैक करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी.
- ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन की स्थिति (सप्लाई साइड इकोसिस्टम और आरएंडडी पर किए गए प्रयास).

यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्यांकन को सक्षम बनाता है, सफलता के प्रमुख कारकों के साथ-साथ लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है.

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

- **राज्यों की EV प्रगति का होगा पारदर्शी मूल्यांकन**
- **आईईएमआई में 16 संकेतक 3 मुख्य विषय शामिल**
- **चार्जिंग, विद्युतीकरण और इनोवेशन की होगी निगरानी**

जियो-ब्लैकरॉक ने पाँच इंडेक्स फंड किए लॉन्च

मुंबई, 5 अगस्त, 2025=* जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने न्यू फंड ऑफरिंग के तहत पाँच इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिए हैं.

नए फंड हैं, जियोब्लैकरॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जियोब्लैकरॉक निफ्टी नेक्सट 50 इंडेक्स फंड, जियोब्लैकरॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड, जियोब्लैकरॉक निफ्टी स्मालकैप 250 इंडेक्स फंड और जियोब्लैकरॉक निफ्टी 8-13 ईयर G-SEC इंडेक्स फंड. न्यू फंड ऑफरिंग 5 अगस्त, 2025 से शुरू होकर 12 अगस्त, 2025 तक चलेगी. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैकरॉक इंक का संयुक्त उद्यम है, जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी.

लॉन्च के मौके पर जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट के सीईओ सिड स्वामीनाथन ने कहा- निवेश के सभी चरणों में निवेशकों की सेवा करना जियोब्लैकरॉक का लक्ष्य है.

रूस से तेल आयात पर भारत का रुख

- **दोहरा मापदंड नहीं चलेगा : विदेश मंत्रालय**
- **यूरोप और अमेरिका खुद भी कर रहे रूस से व्यापार**

नई दिल्ली, 5 अगस्त.भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) की आलोचनाओं के बावजूद रूस से भारत के तेल आयात जारी रखने का पुरजोर बचाव किया है.

मंत्रालय ने कहा कि यक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के कारण भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का आयात राष्ट्रीय आवश्यकता से प्रेरित है और इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए पूर्वानुमानित और किफायती ऊर्जा मूल्य सुनिश्चित करना है. मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत ने रूस से आयात तब शुरू किया जब यूक्रेन संघर्ष के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी. उस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत द्वारा इस तरह के आयात को वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था. विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आलोचना करने वाले देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं, और उनका ऐसा व्यापार कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मजबूरी भी नहीं है. मंत्रालय ने बताया कि 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो था.

महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य का नया दांव !

मुंबई. महाराष्ट्र की राजनिती के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद शरद पवार अब महाराष्ट्र में नया दाव लगाने जा रहे है. इस बार वे ओबीसी भाईयों को साथ लेकर राजनिती के आयाम बदलने कि फिराक में है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार गुट) द्वारा 9 अगस्त को नागपुर में ओबीसी जागृति हेतु एक मंडल यात्रा निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद शरद पवार करेंगे.

यह मंडल यात्रा भाजपा की ओबीसी विरोधी नीतियों और शरद पवार द्वारा ओबीसी समुदाय के लिए किए गए कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निकाली जा रही है. युवा नेता सलिल देशमुख ने बताया कि पहले चरण में यह यात्रा विदर्भ के 11 जिलों में जाएगी और तालुकाओं में सभाएं आयोजित की जाएंगी.

राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए शरद पवार ने राज्य में मंडल आयोग लागू किया था. महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना. कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. आज भाजपा का ओबीसी प्रेम पूतना मौसी जैसा है. शरद पवार ने ओबीसी के लिए क्या किया ? राज्य की जनता को यह बताने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष राज राजापुरकर के नेतृत्व में पूरे राज्य में मंडल यात्रा निकाली जाएगी.

यह यात्रा क्रांति दिवस 9 अगस्त को नागपुर से शुरू होगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार स्वयं इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए उपस्थित रहेंगे, यह जानकारी पार्टी के युवा नेता सलिल देशमुख ने दी.

विरोध करने भाजपा ने निकाली थी कमंडल यात्रा

दूसरी ओर, भाजपा ने ओबीसी आरक्षण का विरोध करने के लिए कमंडल यात्रा निकाली थी. सलिल देशमुख ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा हमेशा से ओबीसी समुदाय के खिलाफ रही है. राजनीति में ही नहीं, शिक्षा और नौकरियों में भी ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने के कई प्रयास किए गए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित देश के सभी विपक्षी दल ओबीसी की जातिवार जनगणना की मांग कर रहे थे. भाजपा ने इसका विरोध किया. अंततः बढ़ते दबाव के कारण, केंद्र सरकार ने ओबीसी की जातिवार जनगणना की घोषणा की. हालांकि, यह जनगणना कब कराई जाएगी, इसकी कोई घोषणा नहीं की गई.

भाजपा-जदयू के नेता बदल रहे पाला

पटना. बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूती देने के लिए कमर कस ली है. इसी कड़ी में रविवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां कई बड़े नामों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

पूर्णिया की मेयर के पति और समाजसेवी जितेंद्र कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस जॉइन कर ली. वहीं, बीजेपी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सह संयोजक कुणाल किशोर सहनी और जेडीयू के प्रदेश महासचिव कुणाल अग्रवाल ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया. इन सभी नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अल्लावरु ने सदस्यता दिलाई. पार्टी नेतृत्व ने इसे आगामी चुनाव के लिए एक मजबूत संदेश बताया.

राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश राजेश राम ने अपने संबोधन में कहा कि जितेंद्र कुमार जैसे सक्रिय समाजसेवी के पार्टी में आने से पूर्णिया में कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर होगी. वहीं, अल्लावरु ने कहा कि कुणाल किशोर सहनी की एंट्री से अति पिछड़ा समाज में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी. जेडीयू से आए कुणाल अग्रवाल को लेकर कांग्रेस को उम्मीद है कि वह युवा वोटर्स को जोड़ने में कारगर साबित होंगे.

केरल में चुनाव से पहले कांग्रेस की समस्या

तिरुवनंतपुरम. केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की चिंता बढ़ रही है. पार्टी के अंदर गुटबाजी कम नहीं हो रही है तो दूसरी ओर भाजपा ऐसी राजनीति कर रही है, जिसका परोक्ष रूप से यह मकसद दिख रहा है कि सीपीएम के नेतृत्व वाला गठबंधन भले जीत जाए लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए.

मुकेश सहनी को एनडीए में आने का खुला ऑफर

नई दिल्ली/पटना, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही हैण् इस बार चर्चा में हैं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें लेकर हम सेक्युलर पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बड़ा बयान दिया है.

सुमन ने न सिर्फ मुकेश सहनी को एनडीए में आने का खुला ऑफर दिया है, बल्कि यह भी कहा है कि उनके समाज के लिए काम सिर्फ एनडीए ही कर सकता है.

दरअसल संतोष सुमन ने अपने बयान में कहा, मुकेश सहनी अब उस दल और उस गठबंधन से ऊब चुके हैंए जहां उन्हें अपेक्षित सम्मान और अवसर नहीं मिल रहा है. ऐसे में अगर वो एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि मुकेश सहनी का समाज. विशेषकर निषाद समुदाय. अब एनडीए की विकासोन्मुखी विचारधारा से जुड़ चुका है और उन्हें भी उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए. हम पार्टी के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि मुकेश सहनी के समाज को आगे ले जाने के लिए केवल एनडीए ही सक्षम है.

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2025/24 दिनांक: 06.08.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

Maharashtra State Mining Corporation Limited

MSMC

(A Government of Maharashtra Undertaking)

Khanikarma Bhavan, Plot No. 7, Ajni Square, Wardha Road, Nagpur-440015

Tel. No. 0712-2253204 to 2253207 Email : info@msmc.gov.in

Website: www.msmc.gov.in Fax : 0712-2253203

e-TENDER NOTICE

Tender No. MSMC/COAL/2025/01

Digitally sealed tenders (Two-Bid System) (as per e-Tendering system published on **https://mahatenders.gov.in**) are invited by Managing Director, Maharashtra State Mining Corporation Ltd. for 'Lifting and Beneficiation of RoM coal and supply of beneficiated coal to Koradi Thermal Power Station of Mahagenco' from SECL command area.

Tender Submission Date: 06-08-2025 to 27-08-2025

Technical Bid Opening Date: 01-09-2025

Tender documents and other details are available on **https://mahatenders.gov.in.**

Managing Director
M.S.M.C. Ltd., Nagpur

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सचूना - दिनांक 01.08.2025

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 15:00 बजे तक ईटेंडर आमंत्रित करते है, जो उसी दिनांक को 15:30 बजे खोली जाएगी। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी वेबसाईट https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकती है। इस टेंडर के लिए कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है। तथा ऐसा कोई मैनुअल ऑफर प्राप्त होता है, तो भी वह मान्य नही किया जायेगा। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो तो वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा, तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगया जायेगा। जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। **निविदा सूचना संख्या**-ET-T-MUI-RSP-23-24 **दिनांक:** 01.08.2025, **कार्य का नाम** - डीजल लोको शेड इटारसी में 17 (सत्रह) एचएचपी डीजल इंजनों के यूनिट इंजेक्टरों की ओवरहालिंग/रिहैबिलिटेशन का कार्य। एक लोकोमोटिव में 16 (सोलह) यूनिट इंजेक्टर होते है।, **कार्य की अवधि**- 12 माह, **निविदा की अनुमानित लागत रू.** - रू. 71,65,978.72 (रूपये इकहत्तर लाख पैंसठ हजार नौ सौ अठहत्तर और बहत्तर पैस मात्र), **निविदा की बयाना राशि रू.** - रू. 1,43,300.00 (रूपये एक लाख तैंतालीस हजार तीन सौ मात्र), **ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.**- कुछ नहीं, **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय**- 25.08.2025, निविदाकर्ता/बिडर के पास क्लास।।। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है एवं IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। केवल पंजीकृत निविदाकर्ता/ बिडर ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते है। ई-टेंडरिंग के दौरान ही सभी दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पेमेंट गेटवे के द्वारा ऑनलाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। बयाना राशि का भुगतान ऑन लाइन मल्टिपल नेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है।

वरि. मं. यां.इंजी(डी)
पश्चिम मध्य रेलवे, इटारसी

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सचूना - दिनांक 30.07.2025

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 15:00 बजे तक ई-टेंडर आमंत्रित करते है, जो उसी दिनांक को 15:30 बजे खोली जाएगी। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी वेबसाईट https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकती है। इस टेंडर के लिए कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है। तथा ऐसा कोई मैनुअल ऑफर प्राप्त होता है, तो भी वह मान्य नही किया जायेगा। इस निविदा में कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो तो वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा, तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगया जायेगा। जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। **निविदा सूचना संख्या**- ET-T-TRANSMISSION-TW दिनांक: 30.07.2025, **कार्य का नाम** - डीजल लोको शेड इटारसी में दो टावर वैगन टाइप मार्क- IV के लिए हिंदुस्तान मोटर्स मेक ट्रांसमिशन सिस्टम मॉडल सी/आरटी-5633, प्रापेलर शाफ्ट के साथ का POH कार्य।, **कार्य की अवधि**- 6 माह, **निविदा की अनुमानित लागत रू**- रू. 25,14,990.58 (रूपये पच्चीस लाख चौदह हजार नौ सौ नब्बे और अटठावन पैसे मात्र), **निविदा की बयाना राशि रू.**- रू. 50,300.00 (रूपये पचास हजार तीन सौ मात्र), **ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.**- कुछ नहीं, **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय** - 21.08.2025 को 15:00 बजे, निविदाकर्ता / बिडर के पास क्लास।।। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है एवं IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। केवला पंजीकृत निविदाकर्ता/बिडर ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते है। ई-टेंडरिंग के दौरान ही सभी दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पेमेंट गेटवे के द्वारा ऑनलाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। बयाना राशि का भुगतान ऑन लाइन मल्टिपल नेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है।

वरि. मं. यां.इंजी(डी)
पश्चिम मध्य रेलवे, इटारसी

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर